अटल बिहारी वाजपेई के राजनैतिक सिद्धांत पर एक अध्ययन

सकारात्मक

Usha Kumari, Research Scholar

Sri Satya Sai University of Technology & Medical Sciences, Sehore, M.P.

Dr. Rafat Afroz Khan, Associate Professor

Sri Satya Sai University of Technology & Medical Sciences, Sehore, M.P.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय कार्यनीति बड़ी ही सकारात्मक है। वे सम्पूर्ण भारत में उसी को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। इस संबंध में 22 मार्च,1998 को उन्होंने अपनी राष्ट्रीय नीति को निम्न प्रकार व्यक्त किया है–

सवाल केवल नई चीजों के उत्पादन का नहीं है। यह चीजें हर दूसरे साल एक नई टेक्नोलॉजी पर सवार हो जाती हैं और फिर तुरन्त उससे भी नई टेक्नोलॉजी, पिछली को धकेलकर, आगे बढ़ जाती है। हमें इस नई दुनिया का सामना करना है। अपने को इससे काटकर नहीं चल सकते। जो देश आर्थिक और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से शक्तिशाली है, वही दुनियाा पर हावी है। हम में से कोई भी, भारत का मामूली दर्जे में बने रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता।

हम इसे बर्दाश्त करें भी क्यों? जो भी संसाधन चाहिए वह सब हमारे पास है। देश के पास विश्व स्तर की प्रतिभा है। नई टेक्नोलॉजी के मामले में भारतीय दुनिया भर में अगली पंक्ति में खड़े हैं। भारत में भी जहां–जहां रास्ते खुल रहे हैं, जैसे साफ्टवेयर उद्योग, अंतरिक्ष अनुसंधान, नई सूचना व संचार

टेक्नोलॉजी आदि में हमारे नौजवान और नवयुवतियां बड़ी फुर्ती से आगे बढत्रकर अपनी जगह बना रहे हैं।

राष्ट्रीय हित सर्वोपति–

विश्व बाजार के इस भंवर और विश्व व्यापर संगठन के उभरते तंत्र में देश के हितों की रक्षा और उसका संवर्धन हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होती चाहिए। इस संबंध में संकोच की जरूरत नहीं है। दुनियाा भर के सारे देश भू–मण्डलीकरण के इस जमाने में यही कर रहे हैं। अपने देश के हितों को अगे बढत्राने और इस संबंध में अपनी क्षमताओं को मजबूत करते जाने का मतलब दुनिया से अपने को काटकर अलग–थलग कर लेना नहीं है। इसका मतलब पूरी तैयारी करने के बाद चुनौतियों को झेलना है। इस तैयारी का एक बड़ा भाग विकास को रोकने वाली नौकरशाही और सरकारी नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था को मुक्ति दिलाना है। मेरी सरकार इस संबंध में पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सकारात्मक वातावरण आवश्यक–

सार्वजनिक जीवन में एक दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ आया है। लोकतांत्रिक चुनावों ने निंरतर टकराव का रास्ता बना दिया है। और बातों के अलावा इससे भी एक–दूसरे के साथ आने और मिलकर काम करने में रूकावट पैदा होती है। फिर भी देश की राजनैतिक परिस्थितियों के इन्हीं दबावों के कारण करने में रूकावट पैदा होती है। फिर भी देश की राजनैतिक परिस्थितियों के इन्हीं दबावों के कारण गठबंधन बनें और सहयोग करें का वातावरण भी बना है। नाकारात्मकता और छुआछूत की राजनीति ने अपनी दौड़ पूरी कर ली। उचित

और अनुचित रास्तों से एक–दूसरें की टांग खीचने की पागल दौड़ ने दुनिया की नजरों में भारत की छवि को बिगाड़ा है। इसके कारण समाज में साम्प्रदायिक व जातीय विघटन और भय का वातावरण फैला है। मैं ईमानदारी से अनुभव करता हूँ कि हमें एक देश के नाते इस विनाशकारी रास्ते को छोड़ देना चाहिए।

हमारी सभ्यता प्राचीन है। यह समन्वय पर आधारित है। यह समझाने–बुझाने पर जोर देती है, केवल सहन करने पर नहीं। इसका निर्माण सभी उपासना पद्धतियों के प्रति गहरे और सक्रिय आदर पर हुआ। हमारे ऋषियों ने कहा है– सभी स्थानों पर गिरने वाली वर्षा की बूंदे जैसे अलग–अलग धाराओं में बहती हुई अन्त में एक ही समुद्र में जा मिलती हैं, उसी तरह सभी लोगों की पूजायें एक ही ईश्वर को प्राप्त होती हैं।

तमिल संत थिरूमूलर ने अपनी रचना 'थिरूमंदिरम्' में कहा है ''औद्रे कुलम्,उर्वाणे देवन्'' हमारा कुल एक है,हमारा ईश्वर एक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सेक्युलरिज्म का यही सही अर्थ है। मेरी सरकार सेक्युलरिज्म की इस अवधारणा से स्पष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। मेरे साथी और मैं इसी परम्परा में पले–बढ़े हैं। हम इसे संजोकर रखना चाहते हैं।

इसी परम्परा के जरिए हम उस चेतना का पुनर्निर्माण करेंगे जो स्वाधीनता–संघर्ष काल की पहचान बन गई थी। तब उसमें देश के सभी कोनों, सभी आस्थाओं और सभी पेशों को मानने वाले लोगों ने शक्तिशाली, आत्मविश्वासपूर्ण और फिर से उभरते हुए भारत के निर्माण के लिए साथ मिलकर काम किया था।

नैतिक मूल्यों के पुनर्प्रतिष्ठापन की नीति–

अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के बहुआयामी संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है। राजनीति में नैतिक मूल्यों के प्रति जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के प्रति वे बड़े ही संवेदनशील होकर कहते हैं–

आज, हमारा देश बहुआयामी संकट से गुजर रहा है। बढ़ती मुद्रास्फीति, कानून व्यवस्था में गिरावट, बुनियादी सुविधाओं का अभाव, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में वृद्धि और उनमें तेजी, सामाजिक तनाव और हिंसा में वृद्धि, हरिजनों, आदिवासियों, महिलाओं पर अत्याचार और अन्य कमजोर वर्गों का दमन, पूर्वोत्तर की विस्फोटक स्थिति, ये सब इस समस्या के विविध कोण हैं, जिनको इन समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई उनके पास इसके लिए समय नहीं है। वे राजनीति की शतरंज पर अपनी चालें चलने में व्यस्त हैं।

देश की समस्या दरअसल नैतिक समस्या है। हमारे सर्वजनिक जीवन का सबसे दुःखद परहलू यह है कि नैतिकमूल्यों को निहित स्वार्थों और सत्ता गठजोड़ की बलि चढ़ा दिया गया है और राजनीति अब पूरी तरह से सत्तालोलुपता का खेल बन गया है। अगर हम इस संकट से उबरना चाहते हैं तो इसकी पहली और सबसे जरूरी शर्त सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों की पुनर्प्रतिष्ठा करना है।

मूल्यों की पहचान के लिए हमें देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र की सीमाओं से हटकर हर औसत भारतीय इन नैतिक मूल्यों जैसे सहिष्णुता, सादा जीवन शैली, कड़ा श्रम और भाईचारे का सम्मान

करता है। आओ हम इन मूल्यों को मजबूत करें और एक नए समाज का निर्माण करें। हालांकि आधुनिक संदर्भ को जरूर याद रखना है। पंडित नेहरू ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल विकास के लिए करिने पर जोर दिया था। देश ने इसमें बहुत प्रगति की है लेकिन देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को इस समृद्धि का लाभ नहीं मिला है। असमानता बढ़ी है। अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी हुई है।

इन विसंगतियों को सुधारता जरूरी है। हम ऐसा तभी कर सकते हैं जब हम भारतीय मूल्यों को प्रगति के आधार पर स्वीकार करें और व्यक्ति खासकर कमजोर व्यक्ति को अपने विकास का केन्द्र मानकर उसका ख्याल करें।

गाँधी जी, जयप्रकाश जी और उपाध्याय जी सभी ने इसी दृष्टिकोण पर बल दिया है। जनता पार्टी के शासन के दौरान अत्योदय और कार्य के बदले अनाज जैसी योजनायें लागू करने के दौरान इसी दृष्टिकोण को स्वीकार किया गया। शोषण और भेदभाव से मुक्त तथा मूल्य आधारित समाज की स्थापना करना बड़ी चुनौती महज गांधी जी का नाम लेकर या हवाई घोषणायें करने से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए सतत् संघर्ष करना होगा। हमें इसके लिए गरीब किसनों, मजदूरों, हरिजनों, आदिवासियों और आबादी के अन्य शोषित वर्गों को एकजुट करना है।

इन वर्गों की संगठित शक्ति ही एक नए समाज का वास्तव में निर्माझा कर सकती है। महात्मा गांधी को विदेशी शासन के खिलाफ संर्घ में इस वर्ग से बहुत ताकत मिली।

साम्प्रदायिक निरपेक्षता की नीति–

भारतीय राजनीति के विवादास्पद विषय सेक्युलरवाद की आलोचना करते हुए उन्होंने उसकी जगह साम्प्रदायिक निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्दों पर विशेष जोर देते हुए अपने विचार निम्न प्रकार रखे हैं–

राज्य इस अर्थ में सेक्युलर होना चाहिए कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और यह कि वह धर्म के आधार पर नागरिकों में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, संविधान के निर्माण के चार दशक बाद सेक्युलरवाद को लेकर इतना तीव्र विवाद क्यों उठ खड़ा हुआ है?

इसके मुख्यतः तीन कारण दिखायी देते हैं। सिद्धांततः यह स्वीकार करते हुए कि भारतीय पकिल्पना का सेक्युलरवाद सर्वधाम समभाव से प्रेरित होगा और धर्म विरोध का रूप नहीं लेगा, प्रशासन द्वारा अपनायी गयी नीतियों और उनके कार्यान्वित करने के ढंग से इस आशंका ने जन्म लिया कि राज्य धर्म को प्रगति के मार्ग में एक रोड़ा समझता है और उसे दूर रखना चाहता है। सर्वधर्म समभाव के मूल में सब धर्मों और उनके मानने वालों के बीच में जो समानता अभिप्रेरित थी, उसका भी व्यवहार में पालन नहीं हुआ। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों समुदायों में, सही या गतलत यह भावना जड़ पकड़ने लगा कि सत्ता की होड़ में राजनीतिक दल तराजू के पलड़ों को बराबर रखने के बजाय कभी एक तरफ और कभी दूसरी तरफ झुका देते हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए छोटे परिवार के आदर्श को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित और निरूत्साहित करने की किसी योजना को इस आधार पर व्यवहार में लाने से इंकार करना कि उसके कुछ वर्गों की धार्मिक

आस्थाओं को ठेस लगेगी, सेक्युलरवाद के सिद्धांत को ही हास्यास्पद बना देता है। प्राचीन काल में विवाद के अवसर पर वधू को ''अष्ट पुत्रवती'' होने का आशीर्वाद। यदि आज की स्थिति में धर्म सम्मत मानकर व्यवहार में लाया जायेगा तो कुछ ही वर्षों में देश की दशा क्या होगी इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

संविधान के निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान सिविल कानून का प्रयास करना है। ऐसा करने में राज्य की अब तक की विफलता ने भी इस धारणा को बनाने में सहायता दी है कि सामाजिक सुधारों की दिशा में भी इसलिए पग नहीं उठाये जा रहे कि उनसे कुछ वर्गों कू असंतुष्ट हो जाने और फलस्वरूप चुनाव में घाटा होने की आशंका है। वन्देमातरम् राष्ट्रगीत के गायन पर आपत्ति भी उस मनोवृत्ति का ही परिचय देती है, जिसकी चरम परिणति भारत के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन में हुई। भारत को ''सेक्युलर'' बनाने के पीछे यह भी भावना थी कि विभाजित भारत अविभाज्य रहेगा और धर्म, जाति, भाषा, के आधार पर बअ किसी नये विभाजन की मांग नहीं उठेगी। देश के भिन्न–भिन्न भागों में विघटनकारी तत्वों के हिंसात्मक उपद्रवों ने एक राष्ट्रीयता की भावना को ठेस पहुँचाई है और कुछ लोग यह सोचने लगे हैं कि 1950 में जो मार्ग चुना क्यों वह सही था? भारत के आसपास होने वाली घटनायें और राजकीय व्यवस्थायें भी जनमानस को प्रभावित करती हैं। विश्व के कुछ भागों में धार्मिक कट्टरता के उदय और आतंकवाद के साथ उसके गठबंधन ने भी नये भयों को जन्म दिया है।

मुझे लगता है कि प्रारम्भ में ही ''सेक्युलर'' का अनुवाद ''धर्मनिरपेक्ष'' के बजाय ''साम्प्रदाय निरपेक्ष'' या ''पंथनिरपेक्ष'' कर दिया जाता तो अनेक आशंकाये जन्म नहीं लेती। ''सेक्युलर'' शब्द के अर्थ के बारे में भले ही भिन्न–भिन्न मत रहे हों किन्तु उस मतभिन्नता में इस बात पर एकता थी कि राज्य का स्वरूप असाम्प्रदायिक होना चाहिए। इस प्रश्न पर आज भी एक मत है। संविधान के नये हिन्दी संस्करण में ''सेक्युलर'' का अनुवार '8पंथनिरपेक्ष'' करके इस भूल के परिमार्जन का प्रयास हुआ है। आवश्यक है कि ''सेक्युलर'' शब्द के सही अनुवार को सब स्वीकार करें और उसे प्रचारित करें।

विश्व के कुछ भागों में धार्मिक कट्टरवाद के उदय और हिंसक आतंकवाद से उसके गठबंधन की आशंकाओं से एक चिन्ताजनक परिस्थिति पैदा हो गई है। भारत के पड़ोस और अन्य देशों में जो कुछ हो रहा है उस सतर्क दृष्टि रखते हुए हमें अपनी संस्कृति और परम्परा पर दृढ़ रहना है। और ऐसे भारत के निर्माण के संकल्पना को व्यवहार में लाना है जिसमें सम्प्रदाय या पूजापद्धति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

सेक्युलरवाद का नारा कोई कांग्रेस पार्टी का नारा नहीं है,इस इस देश की संस्कृति में से निकाला हुआ मंत्र है। क्या भारत की स्वाधीनता के बाद भारत को हिन्दू राज घोषित नहीं किया जा सकता था? पाकिस्तान ने किया, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों? इसलिए कि हमारी संस्कृति उसकी इजाजत नहीं देती। स्वयं हिन्दुत्व में उपासना की अनेकों पद्धतियां हैं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा– एक किताब को मानो, एक व्यक्ति में ईमान लाओं,नहीं तो दोजख में जाना पड़ेगा। सत्य एक है, लेकिन विद्वान लोग भिन्न–भिन्न रूप में उसकी

व्याख्या करते है। परमात्मा एक ही है, लेकिन उसकी प्राप्ति के अनेकानेक मार्ग हो सकते हैं। लेकिन आज सेक्युलरिज्म का मतलब हो गया है– हिन्दू विरोधी। नान–एलाइनमेंट की तरह इस सरकार के सेक्युलरिज्म को भी संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। यह संदेह दूर करना होगा। मुझे अपने हिन्दूत्व पर अभिमान है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं मुस्लिम विरोधी हूँ या इस्लाम से मेरा कोई झगड़ा है। लेकिन जब मजहब के साथ राजनीति को मिलाया जाता है, जब उसके आधार पर सत्ता हथियाने की कोशिश की जाती है, जब आप पृथकता को बढ़ावा देते हैं, जब आप रब्बातके सम्मेलन में जाने का फैसला करते हैं, साम्प्रदायिकता बढ़ती है। यह साम्प्रदायिकता दुधारी तलवार की तरह से है। एक तरफ साम्प्रदायिकता की आग जलाकर, दूसरी तरफ आप साम्प्रदायिकता को शांत नहीं कर सकते। हर एक को अपने गिरहबान में मुंह डालकर देखना चाहिए। राष्ट की एकता को अगर मजबूत करना है तो वह राजनीतिक सौदेबाजी के आधार पर नहीं हो सकती। हमारा देश विविधताओं से परिपूर्ण है,ये विविधतायें हमारे जीवन में समृद्धि का द्योतक है,लेकिन विविधता के मूल में एकता निवास करती है। इस एकता को बलशाली बनाने का नाम भारतीयकरण है।

आर्थिक विकास की नीति–

अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय आर्थिक नीति के बारे में कहा है कि– रेटिंग एजेन्सियों और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों जैसे अन्य संस्थानों के दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली में आमूल परिवर्तन हो।

नयी विश्व वित्तीय संरचना के लिए निम्न 6 रूपी आधार स्तंभ होने चाहिए–

1. अधिक अस्थिरता के बिना विशाल पूंजी प्रवाहों का प्रबन्ध।
2. दुनियां भर में इलेक्ट्रनिक के जरिए तत्काल धन अंतरण को देते हुए फौरन फैसला करना और समय पर उपचारात्मक उपाय करना।
3. विकसित और विकासशील के दोनों ही तरह के देशों में सरकारी तथा अर्थसरकारी, सार्वजनिक, निजी तथा सभी पक्षों में पारदर्शिता।
4. स्वभावतः असमानतापूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था में समानता की प्राप्ति।
5. ''संसर्ग प्रभाव'' के विरूद्ध समय पर निवारक कदम।
6. तेजी से बदलती वित्तीय व्यवस्था में अनुकूलन और नवीनता लाने की क्षमता उत्पन्न करना।

हम शीघ्र ही इसे राष्ट्रीय बहस के लिए रखेंगे, जिसमें विपक्षी दलों तथा व्यापार, उद्योग और श्रमिक सभी वर्गों के विचार आमंत्रित किए जाएंगे। हम वित्तीय प्रणाली के पुनर्गठन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वसम्मति को प्रोत्साहन देने के प्रयास में अन्य देशों के साथ रचनात्मक सम्वाद भी बनाएंगे। केवल विश्व वित्तीय व्यवस्था ही नहीं है जिसमें आमूल पुनर्गठन की आवश्यकता है। हमारी अपनी अ र्थव्यवस्था में भी गहरे,व्यापक और तेज सुधारों की फौरन जरूरत है। मेरी सरकार इस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित है। हमारी प्रतिबद्धता शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म में है। मैं आश्वस्त हूँ कि आर्थिक क्षेत्र में की गई हमारी पहल, हाल की किसी भी सरकार द्वारा

अपने कार्यकाल के पहले छह महीनों में किए गए प्रयासों से कही अधिक बेहतर है।

उदारीकरण की नीति–

इस अवधि में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च प्रगति पथ पर लाने के अपने इरादे को मूर्तरूप में व्यक्त किया है और उदारीकरण के दर्शन व नीतियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के बारे में सभी संदेहों को दूर कर दिया है। मेरी सरकार सुधारों के पूर्ववर्ती सरकारों के किसी भी प्रयास से मुकरी नहीं है। बल्कि सुधार प्रक्रिया को हमने एक नई गति प्रदान की है।

इस पद पर आने से पूर्व भी मेरा निजी विश्वास यह रहा है कि लाइसेंसों, नियंत्रणों और लालफीताशाही को समाप्त किया जाना चाहिए। मेरी सरकार ने चीनी, पेट्रोलियम और कोयला/लिग्नाइट को आई0डी0आर0 अधिनियम के दायरे से बाहर करके लाइसेंस मुक्त किया है। इसके साथ ही केवल सामरिक महत्व के क्षेत्रों के उद्योगों को छोड़कर समूचे भारतीय उद्योग को औद्योगिक लाइसेंसों के दायरे से मुक्त कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी आगमन को सरकार की अनुमोदन–प्रक्रिया से लगभग मुक्त कर दिया गया है, ताकि देश में इनके प्रवाह में सुभीता हो।

संदर्भ सूची

1. वरनी, डगलस वी० (2003): फ्रॉम क्वेजार्ड, फेडरलिज्म टु क्वेंजाई कन्फेडरेसी ? द ट्रांसफोरमेशन ऑफ इण्डियाज पार्टी सिस्टम" पुब्लियस
2. दी जर्नल ऑफ फेडरलिज्म, पृ० 33 (4)
3. ल्वन ज्नइमए प्रधानमंत्री एपीसोड, एबीपी न्युज

4. वरनी, डगलस वी० (2003): फ्रॉम क्वेजार्ड, फेडरलिज्म टु क्वेंजाई कन्फेडरेसी? द ट्रांसफोरमेशन ऑफ इण्डियाज पार्टी सिस्टम" पुब्लियस दी जर्नल ऑफ फेडरलिज्म, पृ० 156
5. राम, डी० सुन्दरः कॉएसिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, सर्च फोर पोलिटिकल स्टेबिलिटि, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2000, प० 135
6. सिंह, एम० पी०: नेशनल फ्रंट एण्ड युनाइटेड फ्रंट कोलिशन गवर्नमेंट', पृ० 83
7. अरोड़ा, बलवीर (2002): 'द पॉलिटिकल एण्ड पार्टी सिस्टम', दएमरजेन्स ऑफ न्यू कोलिशंस, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस
8. चक्रवर्ती, विधुत (2006): फॉरजिंग पावरः कोलीशन पॉलिटिक्स इन इंडिया', नई दिल्ली, ऑक्सफोर्ड युनिवर्सिटी प्रेस
9. रत्ना, डॉ० अनुराग : कोलिशन पोलिटिक्स ए न्यू टर्न टू कन्स्टीट्युशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, उप्पल पब्लिकेशन दिल्ली, पृ० 38
10. रत्ना, डॉ० अनुरागः 'कोलिशन पोलिटिक्स ए न्यू टर्न टू कन्स्टीट्युशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, उप्पल पब्लिकेशन दिल्ली, पृ० 42–43
11. फारूकी, अदनान/श्रीधरन ईश्वरनः 'रिसर्च आर्टिकल, सेंटर फॉर द एडवांस स्टडी ऑफ इण्डिया (सीण्एण्एसण्आईण)', द ट्रस्टी ऑफ द युनीवर्सिटी ऑफ पेंसिलवेनिया